



बिहार विधान सभा

की

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

का

205वाँ प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड से संबंधित कॉडिका संख्या 3.4 पर समिति का 205वाँ प्रतिवेदन ।

(दिनांक _____ ई० को सदन में उपस्थापित) ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन वर्ष 2018-20	क
2. सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण/प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय/विभागीय पदाधिकारीगण/निगम के पदाधिकारीगण ।	ख
3. प्राक्कथन	ग
4. प्रतिवेदन	1-3
5. परिशिष्ट	4-16
6. कार्यवाही	17-20

क

बिहार विधान सभा सचिवालय

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का वर्ष 2018-20 तक की अवधि के लिये गठित माननीय सदस्यों की सूची—

सभापति

1. श्री हरिनारायण सिंह

स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री नरेन्द्र नारायण यादव

स०वि०स०

2. श्री रामदेव राय

स०वि०स०

3. श्री श्रीनारायण यादव

स०वि०स०

4. श्री अनिल सिंह

स०वि०स०

5. श्री ललन पासवान

स०वि०स०

6. श्री नीरज कुमार

स०वि०स०

7. श्री आलोक कुमार मेहता

स०वि०स०

8. श्री मुनेश्वर चौधरी

स०वि०स०

9. श्री रामचन्द्र सहनी

स०वि०स०

10. श्री रामचन्द्र भारती

स०वि०प०

11. श्री संजीव श्याम सिंह

स०वि०प०

12. श्री संजय प्रसाद

स०वि०प०

बिहार विधान सभा सचिवालय

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. श्री बटेश्वरनाथ पाण्डेय | सचिव |
| 2. श्री भूदेव राय | उप-सचिव |
| 3. श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव | अवर-सचिव |
| 4. श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह | सहायक |
| 5. श्री अभितेज कुमार | सहायक |

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय .

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. श्री नीलोत्पल गोस्वामी | प्रधान महालेखाकार |
| 2. सुश्री प्रीति अब्राहम | वरीय उप-महालेखाकार |
| 3. श्री अमित कुमार | ले०प०अ० |
| 4. श्री कुमार विकास | स०ले०प०अ०/कोपू |

नगर विकास एवं आवास विभाग

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. श्री अरविन्द कुमार झा | संयुक्त सचिव |
|--------------------------|--------------|

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह | प्रबंध निदेशक |
| 2. श्री सुधीर कुमार | जी०एम० (एफ०) |
| 3. श्री सुमित | फायनेंस अफसर |
| 4. श्री धीरज कुमार | सी०ए०, एम०एफ० |
| 5. श्री राजीव कुमार | डी०सी०ओ०, डी०पी०डी०, बुडको |

प्राक्कथन

मैं, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की हैसियत से बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की कौटुंबिक संख्या 3.4 पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन संख्या 205वाँ प्रस्तुत करता हूँ।

यह प्रतिवेदन दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड एवं सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने अथक परिश्रम से समिति को जो सहयोग दिया है वह सराहनीय है। इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

समिति के माननीय सदस्यगणों ने अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन तैयार करने में जो सहयोग किया है, मैं उनका आभारी हूँ और इस कार्य हेतु मैं उन्हें अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ।

पटना :

दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 (ई०)।

हरिनारायण सिंह,

सभापति,

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति,

बिहार विधान सभा।

प्रतिवेदन

सी0ए0जी0 का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुये वर्ष के लिए (वाणिज्यिक) प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या-59 एवं 60 पर द्रष्टव्य।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट बेबरेजेज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड तथा बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड

3.4 उपहार पर परिहार्य व्यय

कम्पनियों द्वारा वित्तीय औचित्य की कमी की अवहेलना करते हुए उपहार की सामग्रियों पर ₹ 2.06 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

अभिलेखों के जाँच (नवम्बर 2016 से जून 2017) से यह प्रकट हुआ कि छः सरकारी कम्पनियों ने 2014 से 2016 के दौरान निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार ₹ 2.06 करोड़ के उपहार खरीदें तथा इन्हें विधान सभा/विधान मंडल के सदस्यों, पत्रकारों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को वितरित किया, जिसका विवरण निम्नांकित है :-

क्र० स०	कम्पनी का नाम	वर्ष	सामग्री	मात्रा	राशि (₹ लाख में)	कुल (₹ लाख में)
1	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2014	कलार्ड घड़ी	450	16.00	51.60
		2015	मोबाईल	350	34.97	
2	बिहार राज्य बेबरेजेज निगम लिमिटेड	2016	बीफोर्स	400	10.00	10.00
3	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड	2016	मोबाईल	400	34.00	34.00
4	बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2014	मोबाईल	320	15.42	56.44
		2015	बीफोर्स	363	15.00	
		2016	मोबाईल	400	26.02	
5	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2014	कैमरा	175	18.60	36.31
		2015	कलार्ड घड़ी	175	17.71	
6	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2015	कलार्ड घड़ी	175	17.71	17.71
						20.06

एक कम्पनी के प्रबन्धन अर्थात् बिहार राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड ने बताया (मार्च 2017) कि उपहार की सामग्रियों पर व्यय विभाग¹² के निर्देशानुसार तथा निदेशक मंडल के अनुमोदनोप्राप्त किया गया था ।

कम्पनी का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि यह व्यय वित्तीय औचित्य की कसौटी की अवहेलना करती है तथा यह कम्पनी के उद्देश्यों को बढ़ावा नहीं देती है ।

मामला कम्पनियों (मई 2017 तथा सितम्बर 2017) तथा सरकार (मई 2017 तथा सितम्बर 2017) को प्रतिवेदित किया गया, जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2018) ।

12 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार ।

विभागीय उत्तर

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि० पटना एक कार्यकारी संस्था है जो अपनी स्थापना सहित सम्पूर्ण व्यय स्वयं वहन करने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त सेन्टेज राशि पर निर्भर है। योजनाओं को प्राप्त करने के लिए उक्त संस्था द्वारा वर्ष 2014 से 2016 तक की अवधि में 56.44 लाख रु० को बुडको लोगो युक्त मोबाईल एवं ब्रीफकेस खरीद कर बजट सत्र के दौरान उपहार स्वरूप बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यों के बीच बितरित किया गया था जिसका क्रय निविदा के माध्यम से की गई है एवं इसकी स्वीकृति बुडको के निदेशक मंडल की 30वीं बैठक में ली गई है।

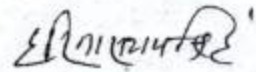
इससे संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक— 2151 दिनांक—19.09.2018 द्वारा महालेखाकार (ले०प०) बिहार, पटना एवं उप सचिव, लोक लेखा समिति की उपसमिति—4 बिहार विधान सभा सचिवालय बिहार पटना को भेजते हुए पत्र की प्रतिलिपि विशेष कार्य पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को भी दी गई है। सुलभ प्रसंग हेतु पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। पृष्ठ 38-48 पर रक्षित ।

नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक— 195, दिनांक— 20.09.2018 द्वारा विभागीय उत्तर प्राप्त ।

समिति की निष्पत्ति / अनुशासना

दिनांक— 24.09.2018 की बैठक में इस कंडिका आपत्ति को निष्पादित किया गया ।

दिनांक— 24.09.2018 की बैठक की कार्यवाही परिशिष्ट पृष्ठ संख्या .
17 से 20 तक पर द्रष्टव्य ।



(हरिनारायण सिंह)

सभापति

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
बिहार विधान सभा ।

पटना :

दिनांक :- 03 दिसम्बर, 2018

परिशिष्ट

संघिका संख्या-6(न०) वि०सा०सा०उप०बै०- 18/2018 195 / न०वि० एवं आ०वि०

श्री अमरेश
24/9/18
प्रेषक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

श्री संजय दयाल,
विशेष सचिव।

सेवा में
श्री भूदेव राय,
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक-20 सितम्बर 2018

विषय:-बिहार विधान सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की मुख्य समिति की दिनांक-
24.09.2018 को निर्धारित बैठक के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्रांक 4756 दिनांक 29.08.2018 के प्रसंग में बिहार विधान सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की मुख्य समिति की दिनांक-
24.09.2018 को निर्धारित बैठक हेतु प्रतिवेदनों की 15-15 प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वात्मजान,

24/9/18

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

बिहार विधान सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की मुख्य समिति की दिनांक- 24.09.2018 को निर्धारित बैठक के संबंध में।

बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्रांक- 4756, दिनांक- 29.08.2018 द्वारा प्रेषित पत्र में अपेक्षित बिन्दु का कड़िकावार प्रतिवेदन।

क्र० सं०	वर्ष	कड़िका	कड़िका का सार	अद्यतन स्थिति
1	2013-14 (वाणिज्यिक)	4.7	परामर्शी को अनुचित फसल- त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं मास्टर सेवा अनुबंध (एम. एस. ए.) के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी की विफलता- परामर्शी को ₹0 3.56 करोड़ के अनियमित भुगतान में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त परामर्शी को अनुचित लाभ का विस्तार फलित हुआ।	विभागीय कार्यालय आदेश संख्या- 389-सह-पठित ज्ञापक- 5323 दिनांक- 12.08.2018 द्वारा त्रिसदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया है तथा इससे संबंधित त्रिसदस्यीय जाँच समिति का निर्णय के आलोक में बुडको के पत्रांक 3351 दिनांक 20.09.2018 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। पृष्ठ 01-37 पर रक्षित।
2	2014-15	2.2.1 से 2.2.23 तक	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि० की संरचनात्मक गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा	विभागीय पत्रांक- 1212 दिनांक- 01.08.2018 द्वारा जाँच समिति का गठन किया गया है तथा इससे संबंधित जाँच समिति का निर्णय प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। मामला प्रक्रियाधीन है।
3	2016-17 (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों)	3.4	उपहार पर परिहार्य व्यय- कम्पनियों द्वारा वित्तीय औचित्य की कसौटी की अवहेलना करते हुए उपहार की सामग्रियों पर ₹0 2.06 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि० पटना एक कार्यकारी संस्था है जो अपनी स्थापना सहित सम्पूर्ण व्यय स्वयं वहन करने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त सेन्टेज राशि पर निर्भर हैं। योजनाओं को प्राप्त करने के लिए उक्त संस्था द्वारा वर्ष 2014 से 2016 तक की अवधि में 56.44 लाख ₹0 को बुडको लोगो युक्त मोबाईल एवं ड्रीफ्ट्स खरीद कर बजट सत्र के दौरान उपहार स्वरूप बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यों के बीच वितरित किया गया था जिसका क्रय निविदा के माध्यम से की गई है एवं इसकी स्वीकृति बुडको के निदेशक मंडल की 30वीं बैठक में ली गई है। इससे संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक- 2151 दिनांक- 19.09.2018 द्वारा महालेखाकार (ले०प०) बिहार, पटना एवं उप सचिव, लोक लेखा समिति की उपसमिति- 4 बिहार विधान सभा सचिवालय बिहार पटना को भेजते हुए पत्र की प्रतिलिपि विशेष कार्य पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार पटना को भी दी गई है। सुलभ प्रसंग हेतु पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। पृष्ठ 38-48 पर रक्षित।

पत्र सं०-07/लोक लेखा 08/2015-2151 न०वि० एवं आ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:-

वैतन्य प्रसाद, मा.प्र.से.,
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

✓ महालेखाकार (ले०प०),
लोक लेखा समिति (अनुभाग), बिहार, पटना।

उप सचिव,
लोक लेखा समिति की उप समिति-4
बिहार विधान सभा, सचिवालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-19/9/18

विषय :- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए का प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) की कड़िका- 3.4 का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाराज,

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए का प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) की कड़िका- 3.4 का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में कहना है कि बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना एक कार्यकारी संस्था है। यह संस्था अपनी स्थापना सहित सम्पूर्ण व्यय स्वयं वहन करता है, जिसके लिए इस संस्था को सरकारी अनुदान अनुमान्य नहीं है। इस कारण ये संस्था अपनी स्थापना सहित सम्पूर्ण व्यय के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त सेन्टेज राशि पर निर्भर है।

योजनाओं को प्राप्त करने के लिए उक्त संस्था द्वारा प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है, जिसके तहत निम्न वर्षों में "बुडको लोगो" युक्त मोबाईल एवं ब्रीफकेस की खरीद कर बिहार विधान सभा/विधान परिषद के माननीय सदस्यों के बीच बजट सत्र के दौरान उपहार स्वरूप वितरित किया गया है :-

क्र० सं०	संस्था का नाम	वर्ष	सामग्री	मात्रा	राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1	बुडको	2014	मोबाइल	338	15.44	15.44	आवश्यक साक्ष्य संलग्न
2		2015	ब्रीफकेस	383	15.00	15.00	
3		2016	ब्रीफकेस	400	26.00	26.00	
कुल योग -						56.44	

उपरोक्त सामग्रियों का क्रय निविदा के माध्यम से की गई है जिसकी स्वीकृति बुडको के निदेशक मंडल की 30 वी बैठक में ली गई है। साक्ष्य स्वरूप निविदा आमंत्रण/निदेशक मंडल की 30 वी बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन एवं अन्य अभिलेख संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उक्त साक्ष्य के आधार पर विषयांकित, कड़िका को विलोपित करने की कृपा की जाय।

अनु०- यथोक्त।

विश्वनाथराज,
19/9/2018
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

शहरा आधारभूत संरचना विकास निगम लि०

(बिहार सरकार का उपक्रम)

खाद्य भवन, दरोगा राय पथ, आर० ब्लॉक, रोड नं०-२, पटना-८००००१

फोन नं०-91-612-2506109/208, 2506132 (फैक्स), email - mdbuidco@gmail.com

-72/LL(VOL-III)-3359

15-12-17

सुसाद सिंह, भा०प्र०से०

दशक.

शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना।

में,

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार पटना।

विषय:- 31 मार्च-2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित कड़िका-An avioable expenditure के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय पत्रांक 07/लो०ले०-08/15-828, दिनांक-30.05.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से मांग किया गया प्रतिवेदन सक्षम साक्ष्य आधारित सत्यापित प्रति के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है।

कृपया ।

अनुलम्बक :- यथोक्त ।

विश्वासमाजन्

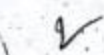
प्रबंध निर्देशक

बुडको बिहार सरकार की एक कार्यकारी संस्था है। बुडको को अपनी स्थापना सहित सम्पूर्ण व्यय स्वयं भारित करना पड़ता है। इस हेतु अधिकाधिक योजनाओं का क्रियान्वयन आवश्यक है ताकि उनसे सृजित सेंटेंज अर्जित किया जा सके।

बुडको द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के संदर्भ में आवश्यक प्रचार-प्रसार के विस्तार हेतु जन-प्रतिनिधियों के बीच सम्बाद आवश्यक है। इस परिपेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2013-2014 में "बुडको लोगो" युक्त मोबाईल एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में सुटकेस की राशि क्रमशः 15.44 लाख रुपये एवं 15.00 लाख रुपये (कुल 30.44 लाख रुपये) बजट सत्र के दौरान बुडको के द्वारा विधान सभा/परिषद के माननीय सदस्यों को उपहार स्वरूप भेंट किया गया था।

- बुडको के पत्रांक-797, दिनांक-19.03.15 में माननीय मंत्री महोदय नगर विकास एवं आवास विभाग के निदेश के आलोक में विधान सभा सत्र के दौरान माननीय सदस्यों को विभागीय सूचना उपलब्ध कराने हेतु बुडको द्वारा अर्जित लाभ (सेन्टेज) से उपहार स्वरूप सुटकेस भेंट करने का उल्लेख है।
- सुटकेस का क्रय निविदा के माध्यम से किया गया था। इसकी स्वीकृति बुडको के निदेशक मंडल की 30वीं बैठक में ली गई थी (प्रति संलग्न)।
- लोगो" युक्त मोबाईल का क्रय निविदा के माध्यम से किया गया था। (प्रति संलग्न)


General Manager (Finance)
BUHDCo


General Manager (Tech)

President, Government of Bihar. BUIDCO will maintain the two parks namely, Nurani bagh and Gauri Shankar Mandir colony park till the parks are handed over to the said Society.

The following resolutions were unanimously passed:

"RESOLVED THAT the CSR policy of BUIDCO be and is hereby approved by the Board"

"RESOLVED FURTHER THAT BUIDCO spend Rs.12 lakhs per annum in CSR activities which is approx. 2% of the average net profit of the company for the preceeding three financial years"

"RESOLVED FURTHER THAT BUIDCO will contribute Rupees Six lakhs seventy six thousand eight hundred per annum in the maintenance and beautification of two parks, namely Nurani bagh Park and Gauri Shankar mandir colony park as its CSR activities till the park is handed over to the Society of Environment and Forest department."

The Managing Director apprised and requested the Board for post facto approval of the purchase of suitcase for the distribution of Budget of Urban Development and Housing Department in the Assembly to the Members and staffs of Legislative Assembly and Legislative Council. The Members reviewed the whole purchase process and passed the following resolution:

"RESOLVED THAT the purchase of suitcase for the distribution to the Members of Legislative Assembly and Legislative Council and their staffs for the presentation of Budget of Urban Development and Housing Department in the Assembly be approved by the Board."

Agenda 30/13

Approval of award of work for the construction of Inter State Bus Terminal at Mauja Pahari, Patna

The Managing Director apprised the Board about the tender floated for the development of Inter-State Bus Terminal at Mauja Pahari, Patna. M/s Pratibha Industries Limited was the qualified and lowest bidder. But it was observed by the Board that the rate quoted by the lowest bidder which was 33.99% more than the estimated project cost. Hence, in the 25th meeting of



बिहार साक्षरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना

(बिहार सरकार का उपक्रम)

303 तीसरा फ्लोर, सोर्या टावर, गोपालीक कॉम्प्लेक्स, बुद्ध मार्ग, पटना-800 001

फोन नं0-91-612-2210101/02, फैक्स नं0-91-612-2210103, Email bi-buidco@gmail.com

अल्पकालीन निविदा सूचना

निविदा सं० :- बुद्धको/वि0-192/15- 103.

दिनांक: 26.03.15

विधान सभा सत्र के दौरान विधान भंडार के गान्धीय सदस्यों को विधायीय सूचना संबंधी कार्यालय उपलब्ध करान हेतु कुल 318 निविदा आमंत्रित की आवश्यकता है:-

Item	Model	Quantity	EMD
VIP Luggage	4 wheeler Trolley, IMPERIA STR (Size-56cm)	318	Rs. 10,000/- (Ten Thousand Only)

उक्त की आपूर्ति हेतु कंपनी के रिटेल आउटलेट/अधिकृत विक्रेता से दिनांक-31.03.15 के उपराह्ण 3:00 बजे तक निगम के मुख्यालय में प्रवेश करने की आवश्यकता है।

- 01 निविदा के साथ प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज, VAT TIN नम्बर, PAN नम्बर, VAT Clearance Certificate संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 02 - पिछले तीन वर्ष (up to f.y. 2013-14) का Income Tax Return संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 03 LOA देने के दो दिनों के अन्दर सागरी की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
- 04 EMD (Refundable) MD, BUIDCO के नाम (Payable at Patna) बैंक डाफ्ट अधिन की राशि के रूप संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा दिनांक 31.03.15 के उपराह्ण 3:30 बजे निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। सागरी की संख्या पटाने/बनाने का अधिकार अथवा बिना कारण बताए प्राप्ति निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

[Signature]
प्रबंध निदेशक



बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना

(बिहार सरकार का उपक्रम)

303 तीसरा तल्ला, मीर्या टावर, मीर्यालोक कॉम्प्लेक्स, बुद्ध मार्ग, पटना-800 001

फोन न०-91-612-2210101/02, फेक्स न०-91-612-2210103, Email id-mdbuidco@gmail.com

शुद्धिपत्र

बुद्धको द्वारा आमंत्रित निविदा सं० : बुद्धको/वि०-192/15-103, दिनांक- 20.03.2015 में अंकित Model

- VIP Luggage, 4 Wheeler Trolley, Imperia Star (Size- 56cm) के स्थान पर Model - American Tourister, Mercury DLX Spinner 56 cm संशोधित करते हुए निविदा प्राप्ति की तिथि दिनांक 02.04.2015 को अपराह्न 03:00 बजे एवं खोलने का समय अपराह्न 03:30 बजे पुनर्निर्धारित किया जाता है। अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

प्रबंध निदेशक

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०

Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd.

मौज टावर / Maurya Tower, बुद्ध मार्ग / Buddh Marg, पटना / Patna-800 001
 Phone : +91-612-2210101, फैक्स नं० / Fax No. : +91-612-2210103
 E-mail : contact@buidco.in, web : http://buidco.in



ISO 9001:2008, 14001:2004

स/No: 50/11-2959

दिनांक/Date: 2/9/14

सेवा में

माननीय मंत्री के आगत सद्वि
 नगर विकास एवं आवास विभाग
 नये सचिवालय पटना

विषय - बुडको द्वारा बिजनेस डेवलपमेंट हेतु मोबाईल सेट उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

प्रतिशय

उपरोक्त विषय में संबंध में सूचित करना है कि बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको), कार्यालय द्वारा बिहार विधान सभा एवं विभिन्न विधान परिषद के माननीय सदस्यों (नाए निर्वाचित सदस्य) को निगम निवेशकों के अनुसार क्वॉट कथ किट मा 338 अटट सैमसंग मोबाईल सेट उपलब्ध करा दिया गया है।

मोबाईल सेट का वितरण सूची		
क्र.सं.	वितरण विवरण	अटट
01	माननीय सदस्य बिहार विधान सभा (नाए निर्वाचित सदस्य)	243
02	अध्यक्ष कोषांग, सचिव एवं उनके कोषांग के लिए	12
03	माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद	73
04	माननीय समापति कोषांग, सचिव एवं उनके कोषांग के लिए	10
कुल		338

अनुलग्नक:- धारिता की छाया प्रति।

सूचनाएं सम्पत्ति।

दिनांक/Date

प्रबंध निदेशक
 बुडको, पटना।

प्रतिनिधि - सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग पटना को सूचनाएं सम्पत्ति।



बिहार सरकार का उपक्रम
 Govt. of Bihar Undertaking

प्रबंध निदेशक

बुडको, पटना का को निवे

बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि० Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd.

मुख्यालय / Maurya Tower, बुद्ध मार्ग / Budhr Marg, पटना / Patna- 800 001
Phone : +91-612-2210101, फैक्स नं० / Fax No. : +91-612-2210103
E-mail : contact@buidco.in, web : http://buidco.in



ISO 9001:2008, 14001:2004

19/01/2014/वि०-50/11-2500

दिनांक/Date : 12-8-14

LETTER OF ACCEPTANCE

To:

M/s Mobile Expo,
Twin Tower,
Gandhi Maidan,
Patna-800001

Sub:- Supply of Mobile Sets 338 (Three hundred thirty eight) Nos of Samsung GT-S-5282 Model.

Ref:- SNIQ number- BUIDCO/V-50/11-49, Dated-19.07.2014

Sir,

This is to notify you that your Quotation dated-26.07.2014 for supply of mobile sets (Samsung GT-S-5282) in BUIDCO under Business Development has been accepted under following terms and conditions

- (i) Your rates Rs 4570 (Rupees four thousand five hundred seventy only) has been accepted
- (ii) All mobile set of Samsung GT-S5282 shall be embossed with BUIDCO official logo.
- (iii) All mobile set shall be uploaded with BUIDCO Logo.
- (iv) All mobile set shall be delivered within a week of issue of LOA to BUIDCO.
- (v) Approved Rates above are including of all taxes.
- (vi) All mobile sets should be strictly in white colour.

Yours sincerely,

(Signature)
(D.S.Mishra)

General Manager (Admin)



बिहार सहकार का उपक्रम
Bihar Sahakar Ka Uyakram

मुख्य कार्यालय: पटना

पता: 101/101/22101003 पंचस तहसीला-22101003 Email id: info@www.balco.in

SNIQ Number: B-222/10.02/11/47 दिनांक 19/12/14

नियम एवं शर्त तथा मोबाइल की दिवसणी एवं अन्य के लिये Website <http://buidco.org> पर निविदा सूचना में देखें।

Sl No	Handset Name	Description	Quantity (Approx)
01	Samsung Model-GT-S-5282	Quad-Band, LCD Full Touch Screen, 2.0 MP Camera, 1GHz Processor, Dual Sim, Android O/s and 3.0 Screen	325 Nos.

दिनांक 26.07.14 को अपराह्न 03:00 बजे तक कोटेशन ऊपर लिखे पते पर जमा कर देना अनिवार्य होगा। प्राप्त कोटेशन उसी दिन अपराह्न 04:00 बजे खोली जायेगी।
निर्धारित समय के बाद प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं की जायेगी।

महाप्रबंधक (प्रशासन) ।

नियम एवं शर्त

1. कंपनी या प्रतिष्ठान को Samsung Authorised Dealer/ Distributor/Store होना अनिवार्य है।
2. रुपये 5,000/- Earnest Money Deposit (Refundable) MD, BUIDCo के नाम से समर्पित करना अनिवार्य है।
3. न्यूनतम तीन वर्षों का Samsung Authorised Distributor/Dealer होना अनिवार्य है।
4. न्यूनतम Annual Turn Over Of Rs. 3.00 Crore होना आवश्यक है।
5. (i) PAN (ii) TIN VAT Number (iii) तीन वर्षों का Income Tax Return (Detailed) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. कोटेशन दो लिफाफे में स्वीकार की जायेगी:
 - (i) लिफाफे के ऊपर तकनीकी कोटेशन अंकित होना चाहिए जिसमें प्रतिष्ठान से संबंधित जानकारी एवं अन्य जानकारी तकनीकी लिफाफा में जमा करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर तकनीकी कोटेशन अंकित किया जाना चाहिए।
 - (ii) वित्तीय प्रस्ताव अलग लिफाफा जिसके ऊपर वित्तीय कोटेशन लिखा होना चाहिए।
5. तकनीकी कोटेशन के साथ संलग्न प्रपत्र भरकर जमा करना अनिवार्य है, तथा उसके साथ दिये गये विवरणों की छायाप्रति भी संलग्न करें।
7. कोटेशन को बिना कारण बताये किसी भी समय रद्द/निरस्त करने या कोटेशन की तिथि एवं समय को परिवर्तन करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
8. Samsung का कार्यालय एवं उसके सर्विस सेंटर, पटना में होना अनिवार्य है।
9. Work Order निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर मोबाईल को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

महाप्रबंधक (प्रशासन)


अतः निवेदन है कि उपरोक्त सूचनायें इस कार्यालय को समर्थित साक्ष्य सहित यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय, ताकि मामले की वास्तविक स्थिति तक पहुँचा जा सके।

भवदीय,

ह0/-
उप-महालेखाकार
सामाजिक प्रक्षेत्र-1/स्थानीय निकाय
बिहार, पटना

सं. एल.ए./डी.पी.सेल/एस.एस.-1/पी.सी.ओ./स्थानीय/1.4.18/24/67 दिनांक: 29.05.2017
प्रतिलिपि अग्रसारित:

1. कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, जहानाबाद
2. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग (UD&HD), बिहार, पटना


उप-महालेखाकार
सामाजिक प्रक्षेत्र-1/स्थानीय निकाय
बिहार, पटना

मधुप/

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की दिनांक-24.09.2018 को 3.00 बजे अपराह्न में
सभा सचिवालय स्थित समिति कक्ष में हुई बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :-

श्री हरिनारायण सिंह	- सभापति
श्री श्रीनारायण यादव	- सदस्य
श्री ललन पासवान	- सदस्य
श्री नीरज कुमार	- सदस्य
श्री आलोक कुमार मेहता	- सदस्य
श्री रामचन्द्र सहनी	- सदस्य

महालेखाकार कार्यालय

सुश्री प्रीति अब्राहम, वरिष्ठ उपमहालेखाकार

श्री अमित कुमार, ले0प0अ0

श्री कुमार विकास, स0ले0प0अ0/कोपू

विभागीय पदाधिकारीगण

श्री अरविन्द कुमार झा, संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग

श्री अमरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रबंध निदेशक, बुडको

श्री सुधीर कुमार, जी0एम0(एफ0)

श्री सुमीत, फायनेंस अफसर

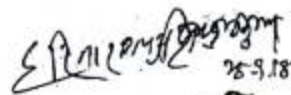
श्री धीरज कुमार, सी0ए0, एम0एफ0

श्री राजीव कुमार, डी0सी0ओ0, डी0पी0डी0, बुडको ।

.....

सभापति : बैठक को कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड से संबंधित कंडिका- 4.7 पर समिति का 204वाँ प्रतिवेदन आज की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया जाता है ।


28-9-18

सभापति
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
बिहार विधान सभा, पटना।

नगर विकास विभाग (बुडको)

सभापति : नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव से प्राप्त पत्र सं० 196 दिनांक- 20.09.18 को समिति के समक्ष रखा गया। आज की बैठक के लिए प्रधान सचिव ने अपनी अनुपस्थिति में श्री अरविन्द कुमार झा, संयुक्त सचिव सह सहायक निदेशक को भाग लेने के लिए प्राधिकृत किया है, समिति इन्हें बैठक में भाग लेने की अनुमति देती है।

वर्ष 2013-14(वा०) की कड़िका 4.7

सभापति : इसका क्या जवाब आया है ?

फायनेंस अफसर : सी०सी०पी०एम० सर्विसेज के लिए रियलाइजेशन टेक्नोलॉजी लि० को एजेन्सी बनाया गया था, उसी से संबंधित कड़िका में ए०जी० की ओर से 5-6 बिन्दुओं पर आपत्ति की गई थी।

सभापति : 3.56 करोड़ अनियमित भुगतान किए जाने के संबंध में क्या कहना है ?

फायनेंस अफसर : डेढ़ साल में एजेन्सी के काम के आलोक में काम के आधार पर 3.30 करोड़ का भुगतान किया गया था। योजना निदेशक के अनुरांसा के बाद ही भुगतान किया गया है। मुख्य आपत्ति थी कि अभियंताओं एवं कर्मियों की उपस्थिति विवरणी नहीं थी। जवाब में है कि उपस्थिति विवरणी कार्यपालक अभियंता द्वारा सर्टिफाइ करके दिया गया था और उसी के अनुसार ही भुगतान हुआ है, अनियमित भुगतान नहीं हुआ है।

वरिष्ठ उपमहालेखाकार : ऐसी बात नहीं है कि आपत्ति सिर्फ उपस्थिति के मामले में ही की गई थी। पहला तो यह था कि कंसल्टेंट के द्वारा काम पूरा नहीं कराया गया, भुगतान किस आधार पर किया गया, अभियंताओं एवं कर्मियों की सूची देनी थी। हमलोगों ने जिस समय आपत्ति की थी, उस समय इस संबंध में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा सका था, आपत्ति के समय एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं था और कंसल्टेंट काम छोड़कर चला गया। परफॉरमेंस गारंटी जो देना था, वह भी प्रोपर-वे में समय पर नहीं किया गया। 15 प्रोजेक्ट्स की क्या स्थिति है ?

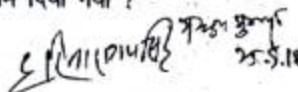
एम०डी० : परफॉरमेंस बी०जी० सबमीट करने के बार ही भुगतान किया गया।

वरिष्ठ उपमहालेखाकार : इसमें काफी विलम्ब किया गया। 15 प्रोजेक्ट्स पूरा नहीं किया, किस आधार पर उनको पेमेंट किया गया, यह कहीं पर डिफाइन्ड नहीं है।

फायनेंस अफसर : एग्रीमेंट में तय था कि कितना उनको मंथली पेमेंट करना है।

श्री ललन पासवान : कोई प्रक्रिया विभाग ने तय किया होगा न ? कोई कमिटी फॉर्म किया या नहीं ?

किस आधार पर इस कंसल्टेंट को काम दिया गया ?

 25.9.18

सभापति
सरकारी उपक्रमों संबंधी सचिव
विहार विधान सभा, पटना।

फायनेंस अफसर : टेन्डर में एल-1 को काम एलौट हुआ । 1 परसेंट जो पेमेंट करना था वह प्रोजेक्ट पूरा होने पर दिया जायेगा । प्रोजेक्ट के आधार पर 1 प्रतिशत का भुगतान नहीं किया गया, सिर्फ मंथली पेमेंट किया गया ।

वरिष्ठ उपमहालेखाकार : ऐक्चुअल वर्क क्या किया उन्होंने प्रोजेक्ट्स पर ?

फायनेंस अफसर : इसका लिस्ट रिपोर्ट साथ दिया गया है ।

वरिष्ठ उपमहालेखाकार : रिपोर्ट की कॉपी अभी मीटिंग स्टार्ट होने के जस्ट पहले दिया गया है । जो सर्विस प्रोवाइड करनी थी, 15 प्रोजेक्ट्स के अन्दर क्या-क्या काम किये, इसका साक्ष्य क्या है ?

फायनेंस अफसर : 15 प्रोजेक्ट्स की मोनिटरिंग करना प्लस डेली ऐक्टिविटी का जो रिपोर्ट दिया उसके आधार पर भुगतान किया गया है ।

संयुक्त सचिव : कौडिका में जो आपत्ति थी, उसके संबंध में तीन लोगों की एक कमिटी प्रधान सचिव के द्वारा बनाई गई थी । उस कमिटी ने जो रिपोर्ट दिया उसके आलोक में बुडको को साक्ष्य और मंतव्य स्पष्ट करने को कहा गया था । विभाग को कमिटी का रिपोर्ट पिछले सप्ताह 20 तारीख को मिला है । विभाग उसकी समीक्षा कर समिति को अपने मंतव्य के साथ रिपोर्ट देगा ।

श्री ललन पासवान : हमने तो शुरू में ही पूछा कि इस संबंध में कोई कमिटी विभाग ने बनाई या नहीं?

सभापति : आपके विभाग में रिपोर्ट आ गया तो कबतक समीक्षा करके समिति को दीजियेगा ?

श्री ललन पासवान : 2013-14 का मामला है, 2016 में विभाग ने कमिटी गठित किया और अभी 2018 तक समिति को विभाग की ओर से रिपोर्ट नहीं आ सका है । इस तरह की परिस्थिति रहेगी तो कैसे विभाग चलेगा ?

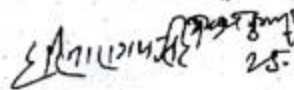
एम0डी0 : एक समय दे दिया जाय, सर । समीक्षा करके फाईनल रिपोर्ट समिति को प्राप्त करा दिया जायेगा ।

सभापति : यह कौडिका लम्बित रहेगा । विभाग शीघ्र फाईनल रिपोर्ट समीक्षा करके अपने मंतव्य के साथ समिति को उपलब्ध कराये ।

वर्ष 2016-17 (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) की कौडिका- 3.4

संयुक्त सचिव : प्रतिवेदन के पेज नं0 38 पर इसका जवाब दिया गया है ।

वरिष्ठ उपमहालेखाकार : उपहार देने के लिए मोबाइल और ब्रीफकेस खरीदा गया, जवाब यह दिया गया कि यह बिजनेस प्रमोशनल एस्पेक्ट था लेकिन फाईल में लिखा है कि माननीय सदस्यों को देने के लिए खरीदा गया है । यह कम्पनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट

 25.9.18

सभापति
सरकारी उपक्रमों संबंधी सचिव
बिहार विधान सभा, पटना

कम्पनी है, उस ऐक्टिविटी में मोबाईल और ब्रीफकेस खरीदकर उपहार दिया गया जो बिजनेस प्रमोशनल ऐक्टिविटी में नहीं आता है।

संयुक्त सचिव : बुडको हमारी वर्किंग एजेन्सी है, हमारे जन-प्रतिनिधि को जानकारी होनी चाहिए कि नगर विकास विभाग का यह एक अनुषांगिक इकाई है जो आधारभूत संरचना विकास हेतु कई काम करता है और एजेन्सी तय करता है। बिजनेस प्रमोशन में माननीय लोगों के लिए वह छोटा-सा गिफ्ट है। इसके कय में जो भी प्रक्रिया होनी चाहिए वह सब किया गया है, टेन्डर के माध्यम से बोर्ड से पारित कर कय किया गया है। विभाग का इसमें कहना है कि किसी प्राइवेट पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए यह उपहार नहीं दिया गया है बल्कि माननीय सदस्यों को प्रसार-प्रचार हेतु जानकारी देने के लिए दिया गया है। इसमें कोई गलत मंशा विभाग की नहीं रही है।

ले0प0 : माननीय सदस्यों के अलावे पदाधिकारियों को भी यह उपहार में दिया गया है।

वरिष्ठ उपमहालेखाकार : हमारा यही कहना है कि इस तरह से गिफ्ट देना कम्पनी के बिजनेस प्रमोशनल ऐक्टिविटी में नहीं आता है।

श्री रामदेव राय : गिफ्ट ही न दिया गया है, कोई बिजनेस तो नहीं किया गया है ?

फायनैस अफसर : बजट प्रस्तुत करने के समय हमलोग जो बजट बनाते हैं, वह सभी मेम्बर्स में बँटता है, कई बुक्स और कागजात उनको देना रहता है जिसे ब्रीफकेस में डालकर विभाग की ओर से दिया जाता है।

एम0डी0 : विभाग की ओर से लिखित जवाब भी दिया गया है। हमलोगों का अनुरोध होगा कि जवाब को स्वीकार करते हुए इस कंडिका को ड्रॉप कर दिया जाय।

सभापति : विभागीय उत्तर के आलोक में समिति द्वारा इस कंडिका को निष्पादित किया जाता है।

तत्पश्चात् बैठक स्थगित हुई।

सभापति
24.9.18
9899999999

सभापति
सकार्य उपकरणों संबंधी समिति
विद्युत विभाग सभा, पटना